ing backward classes; but they are being informed that in the view of the Government of India, it would be better to apply economic tests than to go by caste.

Income-tax Arrears

904. { **Shri Ram Krishan Gupta:**
Shri Chuni Lal:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state the total amount of income-tax arrears as on the 1st April, 1961 according to the Commissioners' charges?

The Minister of Finance (Shri Morarji Desai): The information is being collected and a statement giving the required information will be laid on the Table of the House as early as possible.

Transfer of State Government Employees for Non-Gazetted Central Cadre

905. { **Shri Ram Krishan Gupta:**
Shri Chuni Lal:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 620 on the 8th March, 1961 and state:

(a) whether the details regarding the proposal to fill some vancancies in the non-gazetted cadre classes III and IV under the Central Government by transfer of employees of State Governments have been finalised;

(b) if so, what are they; and

(c) when the proposal will be enforced?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar): (a) to (c). The details of the scheme have not been finalised yet as replies are awaited from some State Governments.

Shuddha Ayurvedic Courses in Banaras Hindu University

906. { **Shri Ram Krishan Gupta:**
Shri Chuni Lal:
Sardar Iqbal Singh:

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 626 on the 8th March, 1961 and state:

(a) whether the scheme to start Shuddha Ayurvedic courses in the Banaras Hindu University has been finalised; and

(b) if so, the result thereof?

The Minister of Education (Dr. K. L. Shrimali): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Utilization of Crude Oil

907. { **Shri Ram Krishan Gupta:**
Shri Chuni Lal:

Will the Minister of **Steel, Mines and Fuel** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 628 on the 8th March, 1961, and state:

(a) whether the scheme for utilisation of crude oil and natural gas from the oil fields of Gujarat has been finalised; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of Mines and Oil (Shri K. D. Malaviya): (a) and (b). The scheme for utilisation of crude oil and natural gas from the Gujerat oil fields is under consideration and its details are being worked out.

Army Excesses in Naga Area

908. { **Shri Ram Krishan Gupta:**
Shri Chuni Lal:
Sardar Iqbal Singh:

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 644 on the 8th March, 1961 and state:

(a) the result of the inquiry ordered into the allegations that certain army personnel had committed excesses in Naga area; and

(b) the action taken thereon?

The Minister of Defence (Shri Krishna Menon): (a) and (b). Both the incidents at PURR and METI-KUMI in the Naga area were investigated by two military Courts of Inquiry. The reports are under examination.

पंजीकृत सहकारी आवास समितियां

९०६. { **श्री खुशवक्त राय :**
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसी पंजीकृत सहकारी आवास सोसाइटियां कितनी हैं जिनके पास भूमि नहीं है;

(ख) उनके नाम क्या हैं;

(ग) उन्हें कितनी भूमि की आवश्यकता है;

(घ) उन सोसाइटियों के नाम क्या हैं जिनको सरकार ने भूमि अर्जित करने का आश्वासन दे रक्खा है; और

(ङ) उन सोसाइटियों के नाम क्या हैं जिनके लिये भूमि अर्जित करने की कार्यवाही की जा रही है और वह कार्यवाही कहां तक पहुंच चुकी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). ऐसी १५५ पंजीकृत सहकारी आवास सोसाइटियों के नामों का, जिन्होंने दिल्ली प्रशासन से भूमि प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र दिये हैं, एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल टी—३०८६।६१]

(ग) लगभग २,००० एकड़ । सोसाइटियों की भूमि सम्बन्धी आवश्यकताओं की अभी जांच की जा रही है ।

(घ) किसी सहकारी आवास सोसाइटी को कोई आश्वासन नहीं दिया गया ।

(ङ) श्री पी० जी० देव द्वारा नियम १९७ के अन्तर्गत दिये गये नोटिस के उत्तर में २३ मार्च, १९६१ को सभा-पटल पर एक विवरण रखा गया । उसमें दिल्ली में भूमि के अर्जन, विकास तथा वितरण सम्बन्धी योजना का विस्तृत विवरण दे दिया गया है । इस योजना के अन्तर्गत आने वाली सारी भूमि प्राप्त की जा रही है । इस भूमि को दिल्ली के व्यवस्थित विकास के लिये प्राप्त किया जा रहा है न कि किसी विशेष आवास सहकारी सोसाइटी के लिये । तथापि यह भूमि प्राप्त करने के पश्चात् ऐसी सहकारी आवास सोसाइटियों आदि को पट्टेदारी के आधार पर वितरित कर दी जायेगी जिनके दावे प्रामाणिक समझे जायेंगे और जो योजना के अंतर्गत आते होंगे ।

सैनिक सामान का उत्पादन

९१०. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में भारत की कुल आर्डनेंस फैक्टरियों में प्रति वर्ष कितना-कितना सामान और किस लागत का (१) फौज के उपयोग के लिये बनाया गया तथा (२) कितना इतर सेना उपयोग के लिये बनाया गया;

(ख) केवल (१) सेना और (२) अन्य प्रयोजनों के लिये कितने मूल्य का सामान बनाया गया;

(ग) जिन आर्डनेंस फैक्टरियों में इतर सेना उपयोग के लिये सामान बनाया गया